रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 115] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 1970/ आषाढ़ 10, 1892

No. 115] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 1970/ASADHA 10, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Administrative Reforms)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st July 1970

No. 8/4/70-P.—The Government of India in the Ministry of Home Affairs (Department of Administrative Reforms) appointed on 5th January 1966, the Administrative Reforms Commission to give consideration to the need for ensuring the highest standards of efficiency and integrity in the public services and for making public administration a fit instrument for carrying out the social and economic policies of the Government and achieving social and economic goals of development, as also one which is responsive to the people.

2 The Administrative Reforms Commission ceased to function with effect from the afternoon of 30th June, 1970, after presenting 20 reports to the Government on various aspects of public administration.

3. Government wish to take this opportunity to place on record their high appreciation of the work done by the Commission.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India, State Governments, Administrations of Union Territories etc.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

L. P. SINGH, Secy

गृह मंत्रालय

(प्रशासनिक सुधार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1970

सं० 8/4/70-पी०.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) ने लोक सेवाओं में सर्वोच्च स्तर की दक्षता तथा सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर विचार करने, सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित करने, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और लोगों की भावनाओं को समझने में उसे समर्थ बनाने के हेतु लोक प्रशासन को उपयुक्त साधन बनाने के लिए 5 जनवरी, 1966 को प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति की थी।

2. प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर सरकार को 20 रिपोर्टें प्रस्तुत करने के बाद 30 जून, 1970 (अपरान्ह) से कार्य करना बन्द कर दिया।

3. आयोग ने जो कार्य किया है उसके लिए सरकार इस अवसर पर आयोग के प्रति उत्कट सराहना की भावना प्रकट करती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों आदि को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

ल० प्र० सिंह, सचिव।

Division
Acc... 1090
Dat... Acc... 5-11-71
Call...
Proc... d
Date of Transfer

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970